



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62242

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1031 वर्ष 2026

राधे

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. दिनांक 10.03.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान आवेदन की सूचना शिकायतकर्ता को उसके पति के माध्यम से दी जा चुकी है।
2. माननीय ए.जी.ए. ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि वर्तमान आवेदन की सूचना शिकायतकर्ता (प्रतिवादी पक्ष संख्या 2) और बाल कल्याण समिति, मेरठ (प्रतिवादी पक्ष संख्या 3) को 18.01.2026 को दी जा चुकी है। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत प्राप्त संबंधी पृष्ठांकन रिकॉर्ड में ले लिए गए हैं। हालांकि, उक्त प्रतिवादी पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उनकी ओर से कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी पक्ष के विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.पी. त्रिपाठी की बात सुनी गई।
4. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 260/2025, धारा 137(2), 351(2), 70(2) बी.एन.एस. और 5जी/6 पॉक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन दौराला, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह घटना 07.08.2025 को घटी बताई जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 18.08.2025 को दर्ज की गई थी। यह देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में अंतर्निहित विसंगतियां हैं क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के आधार

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, नामजद आरोपी विक्कू और एक अज्ञात व्यक्ति पीड़िता को ले गए और जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे धमकी दी गई। हालांकि, पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए अपने बयानों में अपने बयान में काफी सुधार किया है और कहा है कि आवेदक ने नामजद आरोपियों के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। यह तर्क दिया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए बयानों के बीच मौजूद महत्वपूर्ण विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले को इस स्तर पर अविश्वासनीय बनाते हैं। इसके अलावा, चिकित्सा रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है। पीड़िता के शरीर पर किसी भी बाहरी या आंतरिक चोट का कोई निशान नहीं देखा गया। आवेदक ने पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक 30.09.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. माननीय ए.जी.ए. उसने जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन वह रिकॉर्ड में मौजूद उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सका।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, नामजद आरोपी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विकू और एक अज्ञात व्यक्ति ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे धमकाया गया। हालांकि, पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए अपने बयानों में अपने कथन में काफी सुधार किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों के बीच मौजूद महत्वपूर्ण विरोधाभास इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के मामले को निराधार बनाते हैं। इसके अलावा, चिकित्सा रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है। पीड़िता के शरीर पर किसी भी बाहरी या आंतरिक चोट का कोई निशान नहीं देखा गया। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक पांच महीने से अधिक समय से हिरासत में है और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा। इसलिए, मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. उपर्युक्त मामले में आरोपी आवेदक राधे को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए: वह:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24 मार्च, 2026

एसकेटी/-.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।